

प्रेषक,

डा० आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 14 अक्टूबर, 2021

विषय:- केदार स्टेनलेस इण्डिया प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर अजय कादयान पुत्र जगत सिंह कादयान निवासी म० सं०-36 सेक्टर-5 चण्डीगढ़ को औद्योगिक प्रयोजन हेतु 7.0787 है० भूमि कय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-61/जि० भू० व्य० सहा०/2021, दिनांक 06-09-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदक केदार स्टेनलेस इण्डिया प्राईवेट लि० द्वारा निदेशक, श्री अजय कादयान पुत्र श्री जगत सिंह कादयान निवासी म० सं०-36 सेक्टर-5 चण्डीगढ़ द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि विशेष श्रेणी-1(ग) के भूमिधर की भूमि खसरा संख्या-149 रकबा 2.3942 है० खसरा संख्या-150 रकबा 3.6170 है० कुल 02 किते कुल रकबा 6.0112 है० भूमि को छोड़कर संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि खसरा संख्या-148 रकबा 0.5691 है० खसरा संख्या-151 रकबा 2.8857 है० खसरा संख्या-152 रकबा 0.9092 है० एवं खसरा संख्या-153 रकबा 2.7147 है० कुल 04 किते कुल रकबा 7.0787 है० भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ कय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तदकम में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केदार स्टेनलेस इण्डिया प्राईवेट लि० द्वारा श्री अजय कादयान पुत्र श्री जगत सिंह कादयान निवासी म० सं०-36 सेक्टर-5 चण्डीगढ़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु ग्राम शाहपुर, परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार के खसरा खसरा संख्या-148 रकबा 0.5691 है० खसरा संख्या-151 रकबा 2.8857 है० खसरा संख्या-152 रकबा 0.9092 है० एवं खसरा संख्या-153 रकबा 2.7147 है० कुल 04 किते कुल रकबा 7.0787 है० भूमि कय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम दिनांक 15 जनवरी, 2020 की धारा-154(2)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड (उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(V) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

- 2- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।
- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6- इकाई को प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु कच्चा माल एवं तैयार माल के भण्डारण एवं उपयोग हेतु वांछित स्वीकृतियां/अनापत्तियां सक्षम विनिर्दिष्ट अधिकारी से स्वयं प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 7- इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 8- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग निर्धारित प्रयोजन (उद्योग स्थापना) के लिए ही किया जायेगा।
- 9- इकाई राज्य सरकार/शासन के सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त कर उद्योग की स्थापना करेगी।
- 10- भूमि कय करने के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान क्षेत्र के सक्षम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 11- आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 13- सम्बन्धित इकाई द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 14- कय की जा रही भूमि के विक्रय-विलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

- 15- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
 - 16- भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।
 - 17- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
 - 18- सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 19- सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 20- जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या-1161/XVIII(II)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- केदार स्टेनलेस इण्डिया प्राईवेट लि० द्वारा श्री अजय कादयान पुत्र श्री जगत सिंह कादयान निवासी म०सं०-36 सेक्टर-5 चण्डीगढ़।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शर्मा)
अनु सचिव।